आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचती जिंदगियां

डेविड ब्रुक्स

© The New York Times 2019

कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिस एक क्षेत्र में हमारी व्यापक मदद कर सकती है, वह मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है। अनेक संगठन डिप्रेशन का पता लगाने और उसके बारे में मरीजों को बताने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया भर में मानसिक बीमारी की दवा बदलने और आत्महत्याओं को रोकने में सक्षम हो रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में अलग-अलग राय है। कोई इसे डरावना बताता है, तो कोई जटिल। किसी के मुताबिक, इसे जरूरत से ज्यादा महत्व मिला है, तो कोई इसे आश्चर्यजनक बताता है। उदाहरण के लिए, सैनफ्रांसिस्को स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधार्थी इस साल सोचने और बोलने की क्षमता खो चुके लोगों में ब्रेन मॉनिटर स्थापित कर पाने में सफल हुए। इसका उद्देश्य स्ट्रोक, एएलएस या दौरों के कारण बोलने की क्षमता खो चुके लोगों को बातचीत कर पाने में सक्षम बनाना है। यह एक असाधारण उपलब्धि है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिस एक क्षेत्र में हमारी असंदिग्ध मदद कर सकती है, वह मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है। बीमारियों के बारे में पता करने के लिए कई तरह की जांच व्यवस्था है। लेकिन कोई भी जांच ठीक-ठीक यह नहीं बता सकती कि अमुक व्यक्ति को डिप्रेशन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर इतने साधारण होते हैं कि वे किसी व्यक्ति के डिप्रेशन के बारे में नहीं बता सकते, न ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आनेवाले दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। हमारे आसपास बहुत-से ऐसे लोग हैं, जो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन पहले से यह कह पाना बहुत कठिन है कि कौन-सा व्यक्ति खुद को खत्म कर देने के बारे में गंभीर है। बहुत-से लोग तब तक अपना इलाज नहीं करवाते, जब तक उनकी बीमारी गंभीर न हो जाए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ यह है कि इसका इस्तेमाल कर डॉक्टर मरीज को पहले से यह बता पाने में सक्षम हो सकते हैं कि कौन अगले सप्ताह डिप्रेशन में जा सकता है या कौन खुद को मारने की कोशिश कर सकता है। क्राइसिस टेक्स्ट लाइन आत्महत्याओं को रोकने की एक हॉटलाइन है, जिस पर फोन करने के बजाय लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर इस हॉटलाइन से संबंधित संगठन ने करीब दस करोड़ टेक्स्ट मैसेज का विश्लेषण किया है। इस संगठन का लक्ष्य काउंसिलरों की मदद करते हुए उन्हें समझाना है कि किसकी मानसिक बीमारी पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन टेक्स्ट मैसेज का विश्लेषण बेहद दिलचस्प है। हमने यह मान लिया है कि जो लोग उठते-बैठते आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वे

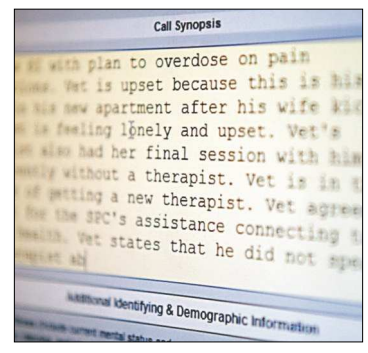

बेहद खतरनाक मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन अध्ययन बताता है कि जो लोग एडविल या इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का बार-बार नाम लेते हैं, उनके आत्महत्या कर लेने की आशंका हमेशा आत्महत्या की बात करने वालों की तुलना में चौदह गुना अधिक होती है। ऐसे ही मैसेज में रोने वाली इमोजी का बार-बार इस्तेमाल करने वाले लोगों को आत्महत्या की बात कहने वाले लोगों की तुलना में मानसिक चिकित्सा की ग्यारह गुना अधिक जरूरत होती है।

अनेक समूह डिप्रेशन का पता करने और उसके बारे में मरीजों को बताने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, लाखों बातचीत सुनने के बाद मशीन डिप्रेशन से पीड़ित मरीजों की शिनाख्त उसके बोलने के लहजे से कर लेती है। क्राइसिस टेक्स्ट लाइन के मुताबिक, अवसादग्रस्त लोग बहुत धीमे-धीमे बोलते हैं और बातचीत में कई बार रुकते या अटकते हैं। मनुष्य की तुलना में मशीनें अवसादग्रस्त रोगियों की शिनाख्त ज्यादा आसानी से कर सकती हैं। देहभाषा या मुद्राओं से भी अवसादग्रस्त रोगियों की शिनाख्त संभव है। ऐसे लोग अपना सिर कम हिलाते हैं और उनके चेहरे पर हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहती। एंड्रयू रेके और क्रिस्टोफर डैनफोर्ड के नेतृत्व में एक शोध टीम ने इंस्टाग्राम पर 166 लोगों की 43,950 तस्वीरें देखीं और बता दिया कि इनमें से कौन अवसादग्रस्त है और कौन नहीं।

मानसिक बीमारियों को मापने के दूसरे तरीके भी हैं। माइंडस्ट्रांग नाम की एक कंपनी स्मार्टफोन के इस्तेमाल के तौर-तरीके देखकर ही अवसाद की पहचान कर लेती है। अपनी किताब *डीप मेडिसिन* में एरिक टोपोल ने यह बताने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह दुनिया भर में मानसिक बीमारी की दवा बदलने में सक्षम हो रहा है। पिछले सप्ताह एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस में मुझे टोपोल से मिलने और बातें करने का अवसर मिला। उनका कहना था कि बीमारियों की पहचान और समाधान सुझाने, सही समय पर जांच करने आदि के मोर्चे पर हम अब भी बहुत पीछे हैं। जब हम किसी रोगी के बारे में डॉक्टर के निष्कर्ष और बीमारी से उस व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो दोनों में भारी फर्क पाते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली दस दवाओं का सेवन दुनिया की तीन चौथाई आबादी करती है। लेकिन इन दवाओं की बिक्री के आंकड़े बीमारी से निदान की गारंटी नहीं हैं। यानी अनेक रोगियों को ये दवाएं गलती से या चिकित्सकों की अज्ञानता के कारण दी जाती हैं। एक दवा या भोजन के एक जैसे चिकित्सकीय निर्देशों से बीमारी का उन्मूलन संभव नहीं है, क्योंकि लोग एक दूसरे बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत बढ़ जाती है।

हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अपरिचित लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये हमारी बातचीत के तरीकों से हमारी भावुक दुनिया के अंदरूनी विवरणों के बारे में जान पाने में सक्षम होंगे।

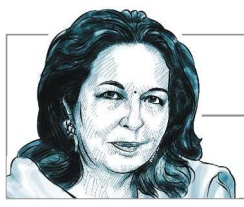

बिंदू डालमिया

दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से उम्मीदें

नई सरकार को बने हुए करीब एक महीना हो चुका है और आते ही वह अपने काम में जुट गई है। अब समय बजट का है, जिसे लेकर काफी उम्मीदें हैं और इस आशावाद की पर्याप्त वजहें भी हैं। सरकार के सामने चुनौती है कि वह कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था की गति तेज करती है, आंतरिक ग्रोथ बढाती है और आर्थिक तौर पर दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभारकर दिखाती है। भारत को मध्य आय अर्थव्यवस्था बनने के लिए सात फीसदी की आर्थिक विकास दर से आगे बढ़कर इसे दोहरे अंकों पर ले जाकर सबको रोजगार देने पर ध्यान देना होगा। अभी सात फीसदी की वृद्धि दर बेशक अच्छी महसूस हो रही हो, लेकिन विकासशील देश को गरीबी से उबरने के लिए ज्यादा वृद्धि चाहिए। लिहाजा सात फीसदी की विकास दर को 10 फीसदी पर पहुंचना चाहिए, फिर साल दर साल इसे आगे बढ़ना चाहिए।

राष्ट्रीय और वैश्विक तौर पर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े हैं। भारत इस साल दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तब भारत की अनुमानित अर्थव्यवस्था तीस खरब डॉलर से ज्यादा की हो सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि हम अपने दरवाजे कारोबार के लिए कैसे खोलते हैं और स्थानीय उद्योगों को कैसे मजबूत करते हैं। भारतीय उद्योग और विदेशी निवेश, दोनों के लिए जरूरत ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार सृजित हो, जो 45 साल में सबसे नीचे है और जीडीपी 2018-19 में 6.8 फीसदी पर है। सरकार इन बड़ी चुनौतियों से वाकिफ भी है, इसीलिए सरकार गठित होने के एक हफ्ते के भीतर ही इसे लेकर दो कमेटियां गठित कर इस पर खास ध्यान देने का संकेत दिया गया।

किसी भी सरकार का पहला बजट सबको खुश करने वाला होना चाहिए। लेकिन मुश्किल समय में कड़े फैसले भी लिए जाते हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार आर्थिक बेहतरी के लिए क्या कदम उठाती है।

चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से भारत को ज्यादा फायदा हो सकता है। हमें पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एहसास कराना चाहिए कि भारत उनके लिए कहीं ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। यहां सप्लाई चेन तो उम्दा है ही, साथ ही यहां राजनीतिक स्थिरता है और श्रम की लागत कम होने के साथ-साथ देश विविधताओं से भरा हुआ भी है।

विकास दर की गाड़ी को पटरी पर लाकर नरेंद्र मोदी को अपने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि यह दर खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। एक बेहतर देश के लिए जरूरी है कि उसकी कंपनियां अच्छा लाभ कमाएं और कर्ज कम हो। उम्मीद है कि वित्त मंत्री मध्यमार्गी, राइट विंग, बिजनेस समर्थकों के साथ इन सारे पहलुओं पर ध्यान देंगी और आगे बढ़ेंगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की मूल सोच भी यही थी।

एनडीए-3 का पहला बजट हमारे ग्रोथ इंजन को हर स्तर पर आगे बढ़ाने वाला रहे। उदाहरण के लिए, खपत बढ़े, निजी निवेश बढ़े और सरकार की काम करने की क्षमता भी बढ़े। एनडीए-2 की नीति भी संरचना और निर्यात सेक्टर को आगे बढ़ाने की थी। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। इस सेक्टर को घाटे से उबारने की जरूरत है। अगर यह क्षेत्र पटरी पर आ गया, तो रोजगार बढ़ेगा और मध्यवर्ग के लोगों के घर की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। इसी तरह सैन्य साजो सामान, टेलीकॉम उपकरण और मोबाइल फोन उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है।

नई वित्त मंत्री को इन बातों पर गौर करना चाहिए। मंदी के मद्देनजर प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाने की जरूरत है। करदाताओं की छूट सीमा पांच लाख रुपये तक होनी चाहिए। ऐसे ही, पीएम किसान जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की जरूरत है, जिसके बारे में चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में व्यवस्था की गई थी। हालांकि बजट में संतुलन बिठाना वित्त मंत्री के लिए वाकई कठिन होगा।

समाज के सभी वर्गों को आर्थिक तौर पर राहत देने की जरूरत है। यानी कर राजस्व के लक्ष्य कम किए जाएं, साथ ही कर आतंकवाद भी खत्म हो। यह 2013 में तब शुरू हुआ, जब आयकर अधिकारियों को अतार्किक राजस्व लक्ष्य दे दिए गए। इसके बाद उन्होंने लोगों को नाहक परेशान करना शुरू कर दिया।

फंड जुटाने के लिए गैर उत्पादक पब्लिक सेक्टर की संपत्तियां बेची जाएं। लेकिन उससे जो फंड इकट्ठा हो, उससे बजट घाटा संतुलित करने का काम नहीं हो, बल्कि उसका इस्तेमाल उत्पादक कामों में हो। ऐसे ही निवेश का इस्तेमाल असरदार तरीके से जनसेवाओं और संरचना में हो।

एनडीए-2 ने आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना पेश की थी। इस पर जीडीपी का 1.3 फीसदी नहीं, बल्कि तीन फीसदी खर्च हो। वहीं शिक्षा में 2.9 की जगह छह फीसदी प्रावधान होना चाहिए। एनडीए-2 ने जिस तरह से सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाईं, आजादी के 75 साल पूरे होने पर उसी तरह की योजना शिक्षित भारत के लिए होनी चाहिए। सबको शिक्षा उसी तरह दी जानी चाहिए, जैसे 2022 तक सबको स्वास्थ्य सुविधा और घर देने का लक्ष्य है।

किसी भी सरकार का पहला बजट सबको खुश करने वाला होना चाहिए। शायद ही कोई सरकार सख्त बजट पेश करना चाहती हो। लेकिन मुश्किल समय में कड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि मोदी आर्थिक तौर पर बेहतरी के लिए क्या करते हैं। इसी आधार पर इतिहास उनका मूल्यांकन भी करेगा।

-नीति आयोग में राष्ट्रीय वित्त समेकित कमेटी की चेयरपर्सन

लेखक और राष्ट्रवाद

रोमा रोलां और रवींद्रनाथ टैगोर के बीच हुए पत्र व्यवहार को एक शताब्दी बाद पढ़ना वाकई काफी दिलचस्प है। कोई भी इन लेखकों की अपने देश की भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता।

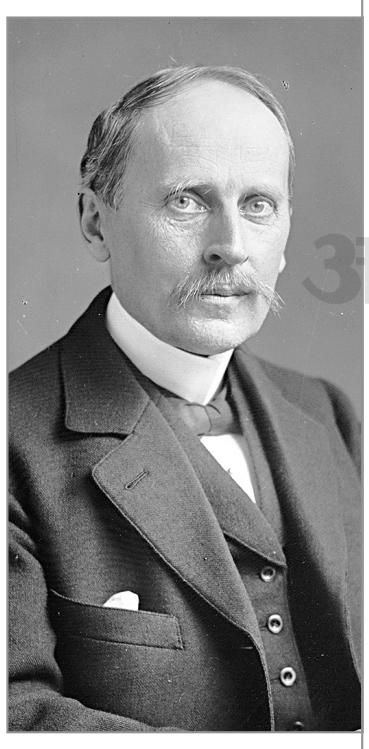

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

करीबन एक शताब्दी पहले, ठीक-ठीक कहें तो 10 अप्रैल 1919 को, फ्रेंच लेखक रोमां रोलां ने बांग्ला लेखक रवींद्रनाथ टैगोर को एक पत्र डाक से भेजा था। वे कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे। दोनों की उनके अपने देशों में और उससे बाहर पर्याप्त ख्याति थी। दोनों को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।

इस पत्र में, जो कि टैगोर को लिखा गया उनका पहला पत्र था, इस फ्रांसीसी शख्स ने इस भारतीय से एक बयान, डिक्लरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ स्पिरिट (आत्मा से मुक्ति का घोषणापत्र), पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया, जिसका मसौदा खुद उन्होंने तैयार किया था। मानव इतिहास का सबसे रक्तरंजित युद्ध अभी-अभी खत्म हुआ था; और लेखकों तथा बुद्धिजीवियों ने इसे भड़काने और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई थी। जैसा कि रोलां ने लिखा, 'विचारकों और कलाकारों ने इस महाविपत्ति में बेहिसाब जहरीली घृणा उड़ेली जो कि यूरोप के शरीर और उसकी आत्मा को नष्ट कर रही है'। बहुत से लेखकों ने खुद को एक राजनीतिक या सामाजिक वंश, एक राज्य, एक पितृभूमि और एक वर्ग के जुनून और अहंकारी हितों का साधन बना लिया था। इन लेखकों की युद्ध में निभाई भूमिका से स्तब्ध और शर्मिंदा होकर रोलां ने इस बयान का मसौदा तैयार किया था, जिसमें उन्होंने उनसे खुद को 'समझौतों', 'अपमानजनक गठबंधनों' और 'गोपनीय दासता' से मुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी भूमिका और हमारा कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि हम भावनाओं के तूफान और अंधियारे के बीच ध्रुवतारे की तरह राह दिखा सकें। इस बयान में लेखकों से कहा गया कि वे खुद को किसी और चीज के बजाय मुक्त सत्य के लिए समर्पित करें, जिसकी कोई सरहद न हो और जो किसी दायरे में सिमटा नहीं हो और जो नस्ल या जातियों के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त हो।

पश्चिम के भीतर रोलां को उनके इस 'डिक्लरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पिरिट' को लेकर अन्य लोगों के साथ जिनका समर्थन मिला उनमें महान इतालवी इतिहासकार बेनेडेटो क्रोस, महान ब्रिटिश दर्शनशास्त्री बर्ट्रेंड रसेल और महान जर्मन उपन्यासकार हर्मन हेस शामिल थे। वह पूर्व से भी हस्ताक्षर चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टैगोर से अपील की। टैगोर ने उन्हें जवाब लिखा कि 'इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाली मुक्त आत्माओं के साथ शामिल होकर उन्हें खुशी हो रही है'।

लेखकों की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर शुरू हुआ यह पत्र व्यवहार कई वर्षों तक जारी रहा। इस पत्र व्यवहार पर हाल ही एक शानदार किताब आई है, *ब्रिजिंग ईस्ट ऐंड वेस्ट*, जिसका संपादन साहित्य इतिहासकार चिन्मय गुहा (इस लेखक से जिनका कोई संबंध नहीं है) ने किया है। जैसा कि यह किताब दिखाती है कि रोलां और टैगोर दोनों ही अपने खुद के देश से गहराई से प्रेम करते थे, इसके बावजूद उन्हें देश के भीतर मौजूद गहरी राष्ट्रवादी भावनाएं पीड़ा देती थीं। फ्रांसीसी अंधराष्ट्रवाद से आहत होकर रोलां स्विट्जरलैंड के विलेनयूवे शहर में जा बसे थे। जैसा कि उन्होंने एक रूसी सहयोगी को लिखा, 'अगर मैं स्विट्जरलैंड में बस गया हूं, तो यह इंगित करना है कि मेरा विचार-केंद्र फ्रांस नहीं है, बल्कि सभी देशों से परे एक सर्वदेशीयता में है, जो सभी जातियों और सभी देशों के सभी मुक्त पुरुषों को गले लगाता है।'

कई वर्षों तक पत्र व्यवहार के अलावा रोलां और टैगोर की यूरोप में कई मुलाकातें भी हुईं। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे; रोलां ने एक साझा मित्र, संगीतकार और रहस्यवादी दिलीप कुमार रॉय से कहा था कि, किसी अन्य जीवित कलाकार ने मुझ पर इतना सहज और आध्यात्मिक प्रभाव नहीं डाला। इस बीच, टैगोर ने एक अन्य साझा मित्र और इतिहासकार कालिदास नाग से कहा, पश्चिम के जितने लोगों से मैं मिला, उनमें रोमां रोलां मेरे दिल और मेरी भावना के करीब थे। टैगोर ने नाग को बताया कि इस फ्रांसीसी की किस चीज ने उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया : 'रोलां जैसे व्यक्ति ने स्वेच्छा से मानवता के कल्याण के लिए तपस्या और शुद्धि को करियर चुना। उन जैसे व्यक्तियों के लिए उनके अपने देश और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं होता। यही वजह है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद के पहरुए उन्हें निशाना बनाते हैं। लेकिन मेरा दिल रोलां और उनके सहयोगियों के छोटे से समूह के साथ है। अंतिम जीत हमारी है क्योंकि हम सत्य के पक्ष में हैं, जिसमें वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति निहित है।'

यह पत्र मई, 1922 में लिखा गया था। उसी महीने टैगोर ने रोलां को लिखा : जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। इसमें संदेह नहीं कि इसने लोगों के दिमागों को भड़का दिया है, लेकिन यह सब संकीर्ण रास्ते से किया जा रहा है और लगातार हमारे साथ गलत कर और ऐसी संस्कृतियों का अपमान कर जो भारत के लिए विदेशी हैं, उन्हें दुष्ट भावनाओं को उभारने का मौका मिल गया है। जो बात मुझे गहराई से कचोटती है, वह यह है कि यह आंदोलन मानवता की एक बड़ी दृष्टि से प्रेरणा लेने में विफल रहा है, लेकिन इसके विपरीत, यह जानबूझकर अनुयायियों के मन में धुंध पैदा कर राष्ट्रीय वैयक्तिकता की चेतना को भड़काने का काम कर रहा है।

रोमां रोलां ने एक बार टैगोर और महात्मा गांधी (जिन्हें वह जानते थे और उनके भी प्रशंसक थे) के बीच दिलचस्प तुलना की। उन्होंने लिखा, इन दोनों महान व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति आदर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से देवदूत और संत की तरह अलग हैं, जैसे सेंट पॉल और प्लेटो।

उम्र बढ़ने के साथ ही रोलां अपने मूल देश से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे थे। दिसंबर, 1937 में उन्होंने टैगोर को लिखा, फ्रांस के कामगार और किसान वर्ग के उभार (सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक) ने मुझे महान सुख और ढेर सारी उम्मीद दी है। विशेष रूप से पिछले दो से तीन वर्षों में वे अपनी एकता और अपनी ताकत को लेकर जागरूक होने के साथ ही विशाल मानवता के प्रति अपनी जवाबदेही को लेकर सजग हुए हैं। इसके अगले वर्ष रोलां स्विट्जरलैंड से फ्रांस वापस आ गए और जंगलों और पहाड़ियों से घिरे छोटे से एक मध्ययुगीन कस्बे में बस गए।

रोलां और टैगोर के बीच हुए पत्र व्यवहार को एक शताब्दी बाद पढ़ना वाकई काफी दिलचस्प है। कोई भी इन लेखकों की अपने देश की भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इनसे समझा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने सार्वजनिक बहसों में हस्तक्षेप किया और किन्हीं खास नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर एक दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि लेखक इसके बावजूद सतर्क थे कि वे किसी राजनीतिक या सामाजिक वंश, या राज्य या पितृभूमि या किसी वर्ग के जुनून और अहंकारी हितों का साधन न बनें।

समृद्धि से लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा चीन?

हमारे सामने वह घट जाता है, जिसकी किसी भविष्यवक्ता ने कल्पना भी नहीं की होती। हांगकांग व्यवस्था परिवर्तन की राह का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसके निहितार्थ भी बहुत बड़े है।

जून 1989 में थियानमेन स्क्वायर बीजिंग में लोकतंत्र की मांग कर रहे करीब चार हजार छात्रों के नरसंहार की पृष्ठभूमि में देखें, तो चीन के लिए प्रस्तावित हांगकांग के प्रत्यार्पण विधेयक का जबर्दस्त जनप्रतिरोध अकल्पनीय है। 75 लाख की आबादी में से 20 लाख लोग सड़क पर हैं। लोकतंत्र के लिए हांगकांग का संघर्ष नया नहीं है। 2014 में 'अम्ब्रेला आंदोलन' के नाम से लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जोशुआ वांग, नाथन ला, एलेक्स चाऊ जैसे सामान्य छात्रों के नेतृत्व में सशक्त आंदोलन चलाया गया था। इस विधेयक के कानून बन जाने पर हांगकांग के नागरिकों को चीन में लंबित मुकदमों में चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता है। यह हांगकांग के लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के लिए बुरी खबर है। यह आंदोलन चीन की अधिनायकवादी सोच को हांगकांग की जनता का जवाब है। अब इसका हमारे लिए क्या निहितार्थ है? चीन यदि लोकतांत्रिक देश रहा होता, तो आज तिब्बत की यह दशा न होती। भारत के साथ फर्जी सीमा विवाद न खड़ा किया गया होता। 'पंचशील' समझौते का सम्मान होता। भारत को घेरने की 'स्टिंग ऑफ पर्ल्स' की रणनीति न होती। बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव के जरिये वैश्विक संसाधनों पर नियंत्रण का अभियान न चलता। वैश्विक विरोध के बावजूद चीन सागर पर वर्चस्व कायम न किया जाता। हमने देखा है कि साम्यवादी सोवियत रूस के विखंडन के बाद यह दुनिया एक बेहतर दुनिया हुई है। चीन का लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने को बाध्य होना विश्व के लिए एक शुभ समाचार है।

आर विक्रम सिंह
पूर्व सैनिक, पूर्व प्रशासक

लोकतंत्र की आहट चीन को उसकी नीतियों के नकलीपन से अवश्य मुक्त कर देगी। तब भारत-चीन संबंध भी यथार्थ के धरातल पर खड़े हो सकेंगे। भारत को पड़ोसियों से उलझाए रखना व उसकी भूमिका को सीमित करना चीनी कूटनीति के लक्ष्य हैं। आज पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और मालदीव चीन के आर्थिक प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित हो चुके है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का संचालन चीनी एजेंसी कर रही है। चीन ने अर्थ का साम्राज्य कायम किया है। बहुत से देश चीनी कर्ज के बोझ के तले, श्रीलंका के समान अपनी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को गिरवी रखने को बाध्य हो रहे है। मोदी सरकार के आने से स्थितियां बदलनी प्रारंभ हुई है। बांग्लादेश की हसीना सरकार भारत चीन मामले में तटस्थ है। श्रीलंका की सिरिसेना सरकार पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे की तुलना में भारत की भूमिका को विशेष महत्व दे रही है। मालदीव से भी चीन के पक्षधर राष्ट्रपति चुनाव हारकर जा चुके है। जरूरी हो रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हमारे पड़ोसी और सुदूर पूर्व के देशों को चीनी प्रभाव क्षेत्र से बाहर ले आने के लिए अमेरिका भारत जापान की धुरी के साथ बिमस्टेक व आसियान के देशों का एक सशक्त आर्थिक संगठन अस्तित्व में आए।

पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के जमाने में, अपनाई गई 'लुक ईस्ट' की नीति प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्गत 'ऐक्ट ईस्ट' की सक्रिय सहयोग की नीति में बदल रही हैं। हमारे सामने रास्ता तो यह है कि हम अपनी 'ऐक्ट ईस्ट' नीति को एक प्रभावी आर्थिक सांस्कृतिक पहल में बदलने का कार्य करें। चीन की अंतरराष्ट्रीय राजमार्गों की योजना के समान यदि वियतनाम, कंबोडिया, थाइलैंड तक के सभी देशों को विशाल राजमार्गों द्वारा भारत से जोड़ दिया जाए, तो इन देशों के आर्थिक हित व्यापार व पर्यटन के माध्यम से सीधे भारत से जुड़ जाएंगे। ये सभी रामायण संस्कृति के देश हैं। रामकथा भिन्न भिन्न रूपों में यहां की संस्कृतियों में रची बसी हैं। जब राष्ट्रों में समृद्धि आती है, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि के साथ अधिनायकवादी तंत्र का नकार होने लगता है। चीन समृद्धि की ओर बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा देश है। जो यात्रा एक कठोर साम्यवादी शासन तंत्र से प्रारंभ हुई थी वह आज पूंजीवाद के चरम पर पहुंच रही है। हांगकांग का यह जन आंदोलन मिस्र में हुए स्प्रिंग आंदोलन की याद दिलाता है, जब काहिरा के तहरीर चौक पर लाखों आंदोलनकारियों ने आवाज उठाई थी। इस आंदोलन ने होस्नी मुबारक की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अभी-अभी जेल से छूटे छात्र नेता जोशुआ वांग के मुताबिक इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है। थियानमेन स्क्वायर और 2014 के छात्र आंदोलन से जगी आजादी और लोकतंत्र की भावना अभी जिंदा है, मरी नहीं है। आंदोलनकारी लिबरेट हांगकांग का प्लेकार्ड लिए जी 20 देशों के दूतावासों में ज्ञापन देते घूम रहे थे कि यह मुद्दा उठाया जाए। हालांकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया जाए।

लोकतांत्रिक चीन अभी बहुत दूर की परिकल्पना है। लेकिन विचारों की शक्तियों को एक सीमा से अधिक नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता। जनआंदोलन अपनी विराटता में बहुत कुछ समेट लेते है। हमारे सामने वह घट जाता है जिसकी किसी भविष्यवक्ता ने कल्पना भी नहीं की होती। हांगकांग, व्यवस्था परिवर्तन की राह का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसके निहितार्थ भी बहुत बड़े है।